(सभी आंकड़े निवल मि० यू० में)

	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
अप्रैल, 92	1845	1649	196	(10.6)
मई	1690	1478	212	(12.5)
जून	1620	1482	218	(13.5)
जुलाई	1590	1333	257	(16.2)
अगस्त	1500	1401	99	(6.6)
सितम्बर	1634	1592	42	(2.6)
अक्टूबर	1880	1837	43	(2.3)

(ख) मध्य प्रदेश में बिजली की कमी होने का मुख्य कारण राज्य में ताप तथा जल विद्युत केन्द्रों से बिजली का कम उत्पादन होना है।

(ग) मध्य प्रदेश में बिजली की कमी सम्बन्धी परिस्थितियों को और कम करने के लिए, बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं। नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जा सकने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों की कार्यदक्षता में सुधार करना, पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा कम करना, मांग प्रबन्धन तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को क्रियान्वित करना तथा बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में बिजली का अन्तरण करने की व्यवस्था करना। पश्चिमी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों के अनाबंटित उत्पादन से भी समय-समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

Clearance of Pench Thermal Power Project, Chhindwara, Madhya Pradesh

1328. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pench Thermal Power Project in Chhindwara District of Madhya Pradesh had been cleared by the Central Authorities and that Madhya Pradesh Electricity Board had even started work on it;

(b) whether it is also fact that after the project was allocated to the Century Group from the House of Birlas for implementing the Project, the Central Authorities have asked the company to seek all the clearances afresh, as per a newsitem which appeared in the Times of India dated the 7th September, 1992 entitled "Power Privatisation" makes no headway;

(c) if so, the details thereof and also the reasons therefor; and

(d) by when the Project is likely to be given final clearance by the Central Government ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Fresh techno-economic clearance from the Central Electricity Authority is required on transfer of a project from State/Central Sector to the private sector. The Private Sector generating company has been asked to furnish certain clarifications and clearances in connection with the fresh techno-economic appraisal of the project. Further details will be available only after the clarifications have been furnished by the Company.

Suspension of work on the Dul-Hasti Hydroelectric Project

1329. SHRI SANJAYA SINH : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work on the Dul-Hasti Hydroelectric project has been suspended since August 24, 1992 as the Frenchmen working there have refused to continue without adequate security as per a news report entitled, "Frenchmen refuse to continue work on Dul-Husti",

which appeared in the Indian Express of the 12th September, 1992;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) what remedial steps Government have taken or propose to take in the matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI) : (a) and (b) The French Consortium executing the Dulhasti Hydro-electric Project on turn-key basis had suspended work on the project since August 24, 1992 following some law and order disturbances in and around the project area, demanding a categorical assurance from the National Hydro-electric Power Corporation (NHPC), about safety and security of their personnel and property. They had recently resumed work with the repairs to the Tunnel Boring Machine (TBM) which had been damaged sometime back due to heavy ingress of water in the tunnel.

(c) A high level team consisting of senior officials of the State Government and security agencies had visited the project site on 30-8-1992 followed by a visit by the Governor of J&K on 31-8-1992 and discussions were held with the French Contractor and NHPC authorities. An assurance of security had been extended to them and security arrangements were augmented to take care of patrolling the 33 km. stretch between Dul and Hasti and the residential colony of the French personnel and the protect area.

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

1330. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अपने कतिपय विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त होने के बारे में गंभीर संदेह है ;

(ख) क्या इस संबंध में विश्व बैंक ने कोई नीति बनाई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भारत को स्वीकार्य और अस्वीकार्य शर्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री प्रेस्टन के भारत आगमन पर उनसे इस मामले पर बातचीत की है, यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) विश्व बैंक से ऋण न मिलने के कारण कौन-कौन से विद्युत संयंत्र/परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगे; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वैकल्पिक योजना बनाई है, यदि हां , तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) "समयमान" (टाइम स्केल) धारणा के अधीन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं का वित्त पोषण किए जाने समेत विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण किए जाने के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने, राज्य बिजली बोर्डों की ओर केन्द्रीय विद्युत निगमों की बकाया राशियों को कम करने और राज्य बिजली बोर्डों को हो रहे घाटे समेत कुछ जारी की गई नीतियों के बारे में बैंक ने सरकार से पुष्टि की इच्छा व्यक्त की है।

(ग) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपने भारत के दौरे के दौरान विद्युत मंत्री से मुलाकात की थी । विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की सरकार की इच्छा से मंत्री महोदय ने अवगत करा दिया है।

(घ) और (ङ) अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ पावर ग्रिड निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं का वित्त पोषण किए जाने के लिए विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है । मूल्यांकन कार्य अलग से भी किया जा रहा है।